हिन्दी दैनिक

इंडिया वार्ता

R.N.I NO. UTTHIN/2011/39104

सच के साथ-जन के साथ

लोकतंत्र में जनसरोकार का सशक्त माध्यम

आत्मिक वाणी

मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना अपने मन मे मेरी बातों को याद रखना क्योकि ऐसा करने से तेरे जीवन के दिन और तेरे वर्ष और बढ़ेगे। तेरा अधिकाधिक कल्याण ही होगा मेरे पुत्र करूणा और सच्चाई कभी तुझ से अलग ना हो तू उनको अपने गले का हार बना कर रखना और उनकों अपने हृदय पटल पर लिख लेना तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में कृपा का पात्र होगा।

थलीसैण उप जिला चिकित्सालय के .. 8

वर्ष : 14 अंक : 260 | देहरादून, गुरूवार 15 मई 2025 | शुल्क : पचास पैंसे | पृष्ठ संख्या : 08

सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का किया गया भव्य आयोजन

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बुधवार को शौर्य स्थल चीड़बाग से गांधी पार्क तक भव्य तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित रही। हजारों की संख्या में आमजन, पूर्व सैनिक, युवा वर्ग एवं मातृशक्ति ने तिरंगे के साथ पद यात्रा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले वीर सैनिकों, वायुसेना, नौसेना और सभी सुरक्षा बलों को नमन करते हुए कहा कि भारत ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने न केवल अपने वीर सपूतों की बहादुरी का प्रदर्शन किया, बल्कि आतंकवाद और उसके समर्थकों को यह स्पष्ट संदेश भी दिया कि नया भारत अब हर आतंकी कार्रवाई का जवाब उसी की भाषा में देगा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत किसी भी आतंकी चुनौती का मुँहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और अब देश की सीमाओं की रक्षा अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक से की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है, जहाँ का लगभग हर परिवार देशसेवा से जुड़ा है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि वे सेना और सुरक्षा बलों के अनुशासन, शौर्य और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में 'तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा' को प्रत्येक वर्ष मनाए जाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक,विधायक श्री खजान दास, श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री बृज भूषण गैरोला, श्री भरत चौधरी, मेयर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल, पूर्व राजसभा सांसद श्री तरुण विजय, भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य कोठारी, महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, दर्जाधारी रजनी रावत, डॉ. देवेंद्र भसीन, श्री श्याम अग्रवाल मौजूद थे।

राज्य सरकार चिकित्सकों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह संवेदनशील : डॉ आर राजेश कुमार

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार से प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ प्रतिनिधिमंडल की सकारात्मक वार्ता, अध्ययन अवकाश पर मिला आश्वासन

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. मनोज वर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार से मुलाक़ात कर चिकित्सा समुदाय से जुड़ी विभिन्न लंबित मांगों पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के विशेषज्ञ चिकित्सकों से संबंधित प्रमुख समस्याओं को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया। वार्ता के दौरान संघ ने विशेष रूप से उन विशेषज्ञ चिकित्सकों के हित में बात रखी जो वर्ष 2016 और 2017 में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) हेतु गए थे। इन्हें अनुमन्य किए गए असाधारण अवैतनिक अवकाश (ईओएल) को अवैतनिक अध्ययन अवकाश में परिवर्तित किए जाने की माँग प्रमुखता से उठाई गई। यह परिवर्तन न केवल सेवा पुस्तिका में स्पष्टता लाएगा, बल्कि चिकित्सकों की वरिष्ठता और भविष्य की प्रोन्नति पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने प्रतिनिधिमंडल की बात को गंभीरतापूर्वक सुना और कहा कि राज्य सरकार चिकित्सकों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। पीजी में गए चिकित्सकों के अध्ययन अवकाश से जुड़ा यह विषय तकनीकी व प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हम इसे यथोचित प्राथमिकता के साथ हल करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। संबंधित विभागों से समन्वय कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन की मंशा है कि चिकित्सकगण बिना अनावश्यक बाधाओं के अपने दायित्वों का निर्वहन करें और उनकी सेवा संबंधित सभी विषयों का निराकरण पारदर्शिता एवं नियमों के अनुरूप किया जाए।

स्वास्थ्य सचिव के इस आश्वासन से चिकित्सा समुदाय में संतोष और भरोसे का वातावरण बना है। इस महत्वपूर्ण बैठक में डॉ. परमार्थ जोशी, डॉ. निशांत अंजुम एवं डॉ. अभिषेक नौटियाल भी उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर चिकित्सा समुदाय में नवीन आशा, विश्वास एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है।

चार आईएएस अधिकारियों के तबादले

देहरादून, इंडिया वार्ता ब्यूरो। उत्तराखंड में एक बार फिर आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया गया है. 10 मई को 25 आईएएस और 13 पीसीएस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल के बाद एक बार फिर उत्तराखंड शासन ने चार आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल कर दिया है। आईएएस अधिकारी निकिता खंडेलवाल को आईटीडीए के निदेशक पद से अवमुक्त कर दिया गया है। शहरी विकास विभाग के निदेशक गौरव कुमार को आईटीडीए निदेशक की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा दो और आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल एजेंसी (आईटीडीए) एक महत्वपूर्ण विभाग है। सभी सरकारी विभागों के वेबसाइट साथ ही सरकारी सिस्टम की डिजिटल प्लेटफॉर्म को तैयार करने के साथ ही सिक्योर करने का भी काम करती है। वर्तमान समय में भारत- पाक के बीच चल रहे तनाव के दौरान साइबर अटैक की संभावना भी बनी हुई है। देश के कुछ जगहों पर साइबर अटैक की सूचनाएं भी आई हैं। इसी बीच उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल एजेंसी के निदेशक को बदल दिया गया है। प्रमुख सचिव एल फ़ैनई को सचिव खाद्य की जिम्मेदारी से अवमुक्त किया गया। आईएएस अधिकारी हरीश चंद्र सेमवाल को सचिव खाद्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में आईएएस हरीश चंद्र सेमवाल बतौर खाद्य आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जिसके साथ ही सचिव खाद्य की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सैनिक और उनके आश्रितों को एक साल मुफ्त परामर्श

देहरादून, इंडिया वार्ता ब्यूरो। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में डॉक्टर सैनिकों एवं उनके आश्रितों को इलाज एवं जांचों में छूट देने लगे हैं। सेलासिटी पॉलीक्लीनिक सेलाकुई की ओर से सैनिकों एवं उनके आश्रितों को एक साल तक मुफ्त परामर्श दिया जाएगा। इसके अलावा खून की जांचों पर 40 फीसदी छूट दी जाएगी। दवाओं पर छूट का प्रावधान किया जा रहा है। यहां पर यूरोलॉजी, मेडिसिन, पीडिया, गायनी और ऑर्थो जैसे विशेषज्ञ डॉक्टरों के परामर्श की सुविधा है। संचालक एवं आईएमए जेडीएन के कन्वीनर डॉ. शुलभ कुडियाल ने कहा कि सीमा पर सैनिक हमारी रक्षा में जुटे हैं। ऐसे में सैनिकों एवं उनके परिवारजनों के लिए मुफ्त परामर्श एवं सस्ती जांच हमारा कर्तव्य ह

सम्पादकीय

जाम से जूझता आम आदमी

राजधानी देहरादून जाम की समस्या आम हो चली है राजधानी में सुबह का समय हो दिन का समय हो या फिर शाम का समय जब देखे आम आदमी जाम से जूझता रहता है उत्तराखंड में राजधानी देहरादून सभी का आकर्षण का केंद्र है इसी के चलते राजधानी देहरादून में आम आदमी जाम से परेशान रहता है शासन प्रशासन ने कई बार शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कमर कसी है लेकिन व्यवस्था सही होने के बजाय उसके विपरीत हो गई है राजधानी देहरादून में नामी-गिरामी स्कूलों के पास अपनी खुद की पार्किंग ना होने का मुख्य कारण है जो जाम की समस्या को पैदा करता है यहां पर स्कूलों का संचालन बड़े पैमाने पर किया जाता है कुछ ही ऐसे स्कूल है जिनके पास अपनी पार्किंग की व्यवस्था है अन्यथा ज्यादा स्कूल सड़कों पर अपनी गाड़ियों को खड़ी करवाते हैं जिसका खामिया शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है सुबह के कप्तान कई बार शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अलग-अलग तरह की दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं बावजूद इसके व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है अभी हाल ही में जिलाधिकारी एवं एस एसपी ने संयुक्त रूप से शहर का भ्रमण किया था उन्होंने खाली पड़ी जगह को चीनी कारण के आदेश दिए थे ताकि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके उन्होंने आदेश दिए थे जितने भी शहर के अंदर जगह खाली पड़ी है उनमें स्थाई रूप में पार्किंग की व्यवस्था की जाए बावजूद इसके अभी तक इस तरह की कोई व्यवस्था शहर में नजर नहीं आ रही है यहां पर डीएम ने एक सराहनीय कार्य किया है मल्टीपल पार्किंग कुछ जगह बनाई गई है जिसमें मुख्य रूप से परेड ग्राउंड के आसपास राजपुर रोड पर इस तरह की पार्किंग बनाई गई है लेकिन व्यवस्था अभी पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है जिसको लेकर शासन एवं प्रशासन को नए तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है जिससे शहर की जनता को जाम से मुक्ति मिल सके।

जिम्मेदार कौन ?

प्रिय पाठकों आप भी एक पत्रकार हो तथा **दैनिक इंडिया वार्ता** की आवाज बन सकते हैं। बस आपको इसके लिए जरूरत है कि हर समय अपनी आंख व कान खुली रखें। चौंकन्ने रहें कि आपके चारों ओर क्या कुछ घटित हो रहा है। नाबालिग बच्चे ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं? स्कूल बंक कर रहे हैं? विकास कार्यों में गड़बडी हो रही है? निर्माण कार्य महीनों से अधूरे पड़े हैं, पाइप लाइन टूटी हैं, घरों में दूषित पेयजल आपूर्ति या महिनों से पानी नहीं आ रहा है। मनरेगा में धांधली हो रही है? आपकी इस प्रकार की समस्याओं को **दैनिक इंडिया वार्ता** जिम्मेदार कॉलम में प्रमुखता के साथ उठाएगा? बस आप उठाइए कलम और तुरंत लिखकर हमें भेजें या फिर संपर्क करें? आपकी आवाज को सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों एवं सम्बन्धित अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा तथा इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल कराने का प्रयास भी किया जाएगा।

संपर्क करें
संपादक
दैनिक इंडिया वार्ता
प्रधान कार्यालय : मोहक्कमपुर खुर्द पोस्ट आई.आई.पी. रेलवे क्रसिंग हरिद्वार रोड़ देहरादून (उत्तराखण्ड)
मोबाईल न.- 7500581414,9359555222
Email: indiawarta@gmail.com

भारत में ज़हरीली शराब से नरसंहार कब तक ?-मृतकों के घर के चूल्हे उजड़ बन रहे मातमगाह-कब जागेगी सरकारें ?

किशन सनमुखदास भावनानीं

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के हर देश के शौकीनों के लिए शराब को एक अमृत रस के रूप में टॉनिक की उपमा दी जाती है। खुशी के अनेकों मौकों पर शराब दावत को देखा जा सकता है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखा हूं कि, नाम मात्र की परमिशन ज़रूर होती है परंतु नियमों विनिमयमों कानूनों की धज्जियां जवाबदेही रखने वालों के नाक के नीचे उड़ती है, बंद लिफाफा होटों पर टेप और आखों पर पट्टी का काम करता है, यह तो हाई प्रोफाइल समिति का उदाहरण है,ठीक वैसे हीबॉटम स्तर पर दारू भट्ठियों, मोहल्ला चौकों,में नंबर दो की तथाकथित नकली एथोनल का उपयोग कर बनाई गई शराब का सेवन मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग करते हैं, यहां भी इन्हीं जवाबदेहों के होटों पर लिफाफे की टेप और आँखों पर पट्टी लगा दी जाती है, जिनके परिणाम स्वरुप पंजाब में बटाला तरनतारन संगरूर जैसे कांड तथा भारत के अनेकों राज्यों में अनेकों केस होते रहते हैं जिनकी चर्चा हम नीचे पैराग्राफ में करेंगे। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहेहैं,क्योंकि दिनांक 13 मई 2025 को पंजाब अमृतसर के पास मजीठा गांव में जहरीली शराब पीने से देर रात्रि 12 तक मेरी जानकारी के अनुसार 21 लोगों की मृत्यु की खबर मीडिया मेंआ चुकी थी। सीएम साहब ने मृत्को के परिवार वालों को 10 लाख रुपयों के मुआवजे की घोषणा की है,व घटना से जुड़े 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) व 105 (गैरइरादतन हत्या) के साथ आबकारी अधिनियम,अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम संबंधी धाराएं लगाई गई है। परंतु मैं एक अधिवक्ता होने के नाते देखता रहा हूं कि नकली जहरीली शराब से जुड़े परिवार वालों के लिए मुआवज़े की घोषणा, आरोपियों की गिरफ्तारी, जमानत, निचली अदालत से ऊपरी कोर्ट तक प्रक्रिया चलती है, तबतक पीड़ित परिवार वालों की जिंदगी शायद समाप्त हो जाती होगी? चूँकि भारत में जहरीली शराब रोकने ऑपरेशन सिंदूर-2 की सख्त ज़रूरत है, तथा सभी राज्यों में एक कॉमन बात कि,नकली शराब से जुड़े परिवार वालों के लिए मुआवजे की घोषणा, आरोपियों की गिरफ्तारी,जमानत बॉटम से ऊपरी कोर्ट तक वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया चलती है तब तक पीड़ित परिवार वालों की जिंदगी शायद समाप्त हो जाती है? इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारत में जहरीली शराब का नरसंहार आख़िर कब तक? मृतकों के घर क़े चूल्हे उजड़ बन रहे मातमगाह, कब जागेगी सरकार? बता दें इस आर्टिकल में दी गई जानकारी की सटीकता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उठाई गई है।

साथियों बात अगर हम दिनांक 13 मई 2025 को जहरीली शराब सेवन कांड की करें तो, अमृतसरपंजाब के अमृतसर जिले के मजीठा ब्लॉक में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई है, जिससे इलाके में मातम छा गया है, यह घटना ब्लॉक के भंगाली कलां,थारीवाल संघा और मरारी कलां जैसे गांवों में हुई। जिला प्रशासन ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है।पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं और 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है जो सप्लायरों से शराब खरीदकर गांवों में बेच रहे थे, इस घटना को लेकर पंजाब पुलिस के महानिदेशक(डीजीपी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि,दुर्भाग्यपूर्ण घटना में नकली शराब के कारण हुई दुखद मौतों के बाद पंजाब पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, जिनमें मुख्य सरगना और कई स्थानीय विक्रेता शामिल हैं, ऑनलाइन खरीदे गए मेथनॉल का इस्तेमाल नकली शराब बनाने में किया गया था। पूरे मामले की जांच चल रहीहै, ताकि कार्य प्रणाली का पता लगाया जाए और सभी दोषियों को न्याय के कठघरे में लाया जाए। साथियों बात अगर हम भारत में जहरीली शराब क़े कहर की करें तो,2014 से 2022 तक किस साल कितनी मौतें हुई, (1) 2014 अवैध शराब के सेवन से 1,699 मौतें हुईं। (2) 2015 1,624 घटनाओं में 1,522 लोगों की जान गई. महाराष्ट्र (278), पुडुचेरी (149) और मध्य प्रदेश (246) में सबसे ज़्यादा मौतें हुईं। (3) 2016 1,073 घटनाओं में 1,054 मौतें दर्ज की गईं. मध्य प्रदेश (184) और हरियाणा (169) में सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। (4) 2017 1,497 घटनाओं में 1,510 मौतें हुईं. कर्नाटक (256), मध्य प्रदेश (216) और आंध्र प्रदेश (183) में हालात गंभीर रहे। (5) 2018 1,346 घटनाओं में 1,365 लोगों की जान गई,मध्य प्रदेश (410) और कर्नाटक (218) में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। (6) 2019 1,141 घटनाओं में 1,296 मौतें हुईं. मध्य प्रदेश (410) और कर्नाटक (268) में स्थिति चिंताजनक बनी रही। (7) 2020 931 घटनाओं में 947 लोगों की जान गई. मध्य प्रदेश (214) और झारखंड (139) में सबसे ज़्यादा मौतें हुईं। (8) 2021 708 घटनाओं में 782 मौतें हुईं। उत्तर प्रदेश (137) और पंजाब (127) में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। (9) 2022 507 घटनाओं में 617 मौतें हुईं। बिहार (134) और कर्नाटक (98) में अवैध शराब का कहर जारी रहा। साथियों बात अगर हम मजीठा कांड में लगाई गई भारतीय न्याय संहिता की धाराओं को समझने की करें तो,भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में धारा 103 हत्या के लिए सजा का प्रावधान करती है, जबकि धारा 105 गैर-इरादतन हत्या के लिए सजा का प्रावधान करती है। धारा 103 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है, तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 105 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति हत्या की श्रेणी में न आने वाला गैर-इरादतन हत्या करता है, तो उसे आजीवन कारावास या 5 से 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 103

हत्या के लिए सजा (1) यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है, तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। (2) यदि पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्यको मृत्युदंड या आजीवनकारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा।

साथियों बात अगर हम अवैध शराब बनने को समझने की करें तो, कैसे बनती है अवैध शराब?कच्ची शराब बनाने के लिए मुख्य रूप से गुड़, पानी और यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कई खतरनाक केमिकल भी मिलाए जाते हैं, गुड़ को सड़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जाता है, अधिक नशा लाने के लिए नौसादर और यूरिया भी मिलाया जाता है, ये सभी चीजें मानव शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक हैं।यूरिया,ऑक्सी टोसिन, गुड़ और पानी को मिलाकर जब फर्मेंटेशन किया जाता है तो इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल बन जाता है,मिथाइल अल्कोहल बनने का एक कारण शराब बनाने की प्रक्रिया के दौरान तापमान का सही ध्यान न रखना भी है, इसी मिथाइल अल्कोहल के कारण शराब जहरीली हो जाती है,इसे पीने से होती है मौत-विशेषज्ञों के अनुसार, मिथाइल अल्कोहल शरीर में जाकर फार्मेल्डिहाइड (फॉर्मिक एसिड) बनाता है, यह एक ऐसा जहर है जो आंखों की रोशनी छीन सकता है या मौत का कारण बन सकता है, यह शराब पीने वाले के दिमाग के लिए भी बेहद हानिकारक है, यदि शराब में मिथाइल अल्कोहल की मात्रा 90 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो वह जहरीली बन जाती है, इतनी मात्रा में मिथाइल अल्कोहल का सेवन नर्वस ब्रेकडाउन का कारण बनता है। 13 मई को बटाला में हुए शराब कांड में पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि नकली शराब बनाने के लिए इस्तेमाल 'मेथेनॉल' थोक में ऑनलाइन खरीदा गया था। मेथनॉल' एक हल्का, रंगहीन कार्बनिक रासायनिक यौगिक है, जिसे अकसर अवैध रूप से मादक पेय पदार्थों में 'इथेनॉल' के सस्ते विकल्प के रूप में ही मिलाया जाता है। साथियों बात अगर हम शराब पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध के बारे में समझने की करें तो,शराब पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध के बारे में क्या? क्या यह सैद्धांतिक रूप से संभव है? यदि ऐसा है, तो केंद्र सरकार शराबबंदी कैसे लागू कर सकती है? खैर, यह देखते हुए कि संविधान संघ को शराब को विनियमित करने की अनुमति नहीं देता है, (केंद्र) सरकार को दो-चरणीय प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होगी। तत्काल कदम संविधान में संशोधन करना और शराब को राज्य सूची से संघ सूची में स्थानांतरित करना होगा। इस तरह के संशोधन के लिए प्रत्येक सदन में एक विधेयक पारित करने कीआवश्यकता होगी, जिसे सदन के अधिकांश सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जिसमें कम से कम 2/3 सदस्य उपस्थित और मतदान करेंगे।

दुर्गम प्रथम के संकल्प को साकार करते हुए डीएम सविन ने लाखामंडल में लगाया जन दरबार, मौके पर ही किया शिकायतों का निपटारा

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री के %दुर्गम प्रथम% के विजन को आगे बढ़ाते हुए, जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज यमुना किनारे बसे दूरस्थ क्षेत्र लाखामंडल में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया। इस %डीएम दरबार% में ग्रामीणों ने अपनी 76 समस्याएं और शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।

सरल स्वभाव, जनहित में त्वरित कार्रवाई और कड़े निर्णय लेने की अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाने वाले डीएम सविन बंसल ने स्वयं प्रत्येक शिकायत को ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उनके निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

शिविर में स्वास्थ्य सेवाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया। 591 से अधिक लोगों की नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच की गई और मौके पर ही 15 आयुष्मान कार्ड तथा 01 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया। इसके अतिरिक्त, कृषि विभाग के लाभार्थियों को 3 लाख 4 हजार रुपये के चेक भी वितरित किए गए।

ग्रामीणों ने मुख्य रूप से सड़क, पेयजल, विद्युत, सिंचाई नहर, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त संपत्तियों का पुनर्निर्माण, जन्म प्रमाण पत्र, आर्थिक सहायता और मुआवजे से संबंधित समस्याएं रखीं। लाखामंडल से नाडा और गोराघाटी से लाखामंडल मोटर मार्ग की खराब स्थिति और लाखामंडल से चकराता मोटर मार्ग के डामरीकरण न होने की समस्या पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सुधारीकरण का कार्य प्रगति पर है। कुन्ना डाटा मोटर मार्ग पर बागवानी क्षति के मुआवजे के लिए एक वर्ष से चक्कर लगा रहे पीतांबर दत्त के मामले में डीएम ने पीडब्ल्यूडी और जिला उद्यान अधिकारी को 10 दिन के भीतर संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

क्षेत्रवासियों ने लाखामंडल से चकराता तक रोडवेज बस सेवा शुरू करने और न्याय पंचायत रेगेऊ में कृषि बीज निवेश केंद्र स्थापित करने की भी मांग की। सिंचाई नहरों से संबंधित शिकायतों की अधिकता को देखते हुए जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को तत्काल शिकायतों का समाधान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, जिनका जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया और जनता से जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा स्टॉल पर 96 लोगों और एलोपैथिक चिकित्सकों द्वारा 495 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर मुफ्त दवाएं वितरित की गईं। समाज कल्याण विभाग ने 10 वृद्धावस्था और 02 दिव्यांगजनों की पेंशन स्वीकृत की, 05 यूडीआईडी कार्ड, 30 वृद्धजनों को सहायक उपकरण और 02 दिव्यांगों को व्हीलचेयर सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए। पंचायती राज विभाग ने 23 परिवार रजिस्टर की नकल, 08 निरस्तीकरण प्रमाण पत्र, 08 राशन कार्ड निरस्तीकरण और 19 नए राशन कार्ड के आवेदन लेने के साथ ही 17 जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित 75 लोगों को लाभान्वित किया। राजस्व विभाग ने 10 आय, जाति और स्थायी प्रमाण पत्र जारी किए।

कृषि विभाग ने 61 लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि, कृषि यंत्र और रसायन वितरित किए, जबकि उद्योग विभाग ने 31 लोगों को औद्यानिक औजार, सब्जी बीज और कीटनाशक दवाएं प्रदान कीं। पशुपालन विभाग ने 25 पशुपालकों को पशु रोगों की रोकथाम के लिए मुफ्त दवाएं वितरित कीं। सहकारिता विभाग ने 07, पर्यटन विभाग ने 09 लाभार्थियों और श्रम विभाग ने 30 श्रमिकों का श्रम कार्ड पंजीकरण और नवीनीकरण किया। बाल विकास विभाग ने 06 महालक्ष्मी किट, 12 किशोरी किट और 09 बेबी किट वितरित किए। पूर्ति विभाग ने राशन कार्ड संबंधी 19 शिकायतों का निस्तारण किया, सेवायोजन विभाग ने 54 युवाओं की करियर काउंसलिंग की और वन विभाग ने वनाग्नि रोकथाम की जानकारी दी।

इस अवसर पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री के संकल्प और जनता के विश्वास को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं की समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान करने के निर्देश भी दिए।

शिविर में उपाध्यक्ष जनजाति सलाहकार परिषद गीताराम गौढ़, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता सिंह, एसडीएम सोहन सिंह रांगड, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा, मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढौंडियाल सहित कई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। मंच का संचालन लाखामंडल समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व बीडीसी सदस्य सुशील गौढ़ ने किया।

भाजपा नेता विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान — मोदी भाजपा का महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब : ज्योति रौतेला

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती ज्योति रौतेला ने भाजपा के नेता विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी का घिनौना और निंदनीय अपमान करने की कड़ी निंदा की है। यह न केवल भारतीय सेना की गरिमा का अपमान है, बल्कि भारत की बेटियों के आत्मसम्मान पर सीधा हमला है। विजय शाह ने अपनी घटिया सोच और घटिया बयान से यह साबित कर दिया है कि भाजपा की मानसिकता हमेशा महिलाओं और उनके सम्मान के खिलाफ रही है।

कर्नल सोफिया कुरैशी न केवल देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया, बल्कि उन्होंने भारत की महिलाओं को सशक्तिकरण का प्रेरणादायक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। उनका अपमान सीधे तौर पर भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता और जातिवाद को उजागर करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा बार-बार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के खोखले नारे लगाते हैं, लेकिन जब बात किसी महिला के सम्मान की आती है — विशेषकर यदि वह एक सशक्त और सक्षम महिला हो — तो उनके प्रवक्ता और नेता बिना किसी शर्म के जहरीले शब्दों से हमला करते हैं। यह संघ प्रेरित मानसिकता अब भी महिलाओं को सिर्फ एक औजार और शोभा की वस्तु मानती है। विजय शाह के इस बयान ने यह साबित कर दिया कि भाजपा का बेटी बचाओ अभियान सिर्फ दिखावा है, असल में वह महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन है।

प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती ज्योति रौतेला का यह स्पष्ट मत है कि अब यह अपमान सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा यह प्रदर्शन केवल कर्नल सोफिया कुरैशी के सम्मान की रक्षा के लिए नहीं है — यह भारत की हर बेटी, हर महिला के आत्मसम्मान की लड़ाई है। हम भाजपा और उनके प्रवक्ताओं से साफ-साफ कह रहे हैं कि अब यह चुप्प नहीं रहेगी। हम इस अपमान के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करेंगे।

उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि

1. भाजपा के जिम्मेदार नेताओं द्वारा दिए गए इस आपत्तिजनक बयान पर तत्काल सार्वजनिक माफी मांगी जाए,

2. दोषी प्रवक्ताओं को पार्टी से निष्कासित किया जाए,

3. महिलाओं के प्रति बार-बार दोहराए जा रहे अपमानजनक रवैये पर प्रधानमंत्री स्वयं स्पष्ट बयान दें।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड महिला कांग्रेस यह स्पष्ट करना चाहती है कि हर महिला की गरिमा की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी अंतिम साँस तक लड़ेगी। इस अवसर पर उर्मिला थापा, सुशीला, पुष्पा पंवार, चंद्राकला नेगी, निधि नेगी, मीना शर्मा, सुनीता कश्यप, अनुराधा तिवारी सहित दर्जनों महिलाएं उपस्थित रही

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक तिरंगा सौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन

देहरादून, इंडिया वार्ता ब्यूरो। भारतीय सेना के शौर्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्मान में देहरादून में नागरिक तिरंगा सौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन हुआ। यह 4 किलोमीटर लंबी यात्रा मुख्यमंत्री आवास से गांधी पार्क तक निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट, मंत्रीगण, विधायकगण, उपाध्यक्ष मैडम रजनी रावत सहित 15,000 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया। यह यात्रा ऑपेरेशन सिंदूर और सीमाओं की रक्षा में सेना के पराक्रम को सम्मान देने हेतु आयोजित की गई थी। इसमें पूर्व सैनिकों, स्कूली छात्रों, युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय के नारों के साथ लोगों ने देशभक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के प्रति जनता ने आभार व्यक्त करते हुए एकजुटता का संदेश दिया।

अगर महिलाएं आईएएफ में राफेल उड़ा सकती हैं, तो सेना की कानूनी शाखा में इतनी कम क्यों ?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

नईदिल्ली,एंजेंसी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि यदि भारतीय वायुसेना में एक महिला राफेल लड़ाकू विमान उड़ा सकती है, तो सेना की जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) शाखा के लिंग-तटस्थ पदों पर इतनी कम महिला अधिकारी क्यों हैं? अदालत ने 50-50 चयन मानदंड पर केंद्र के तर्क पर सवाल उठाया।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने 8 मई को दो अधिकारियों- अर्शनूर कौर और आस्था त्यागी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में मेरिट में क्रमशः 4वां और 5वां स्थान हासिल करने के बावजूद महिलाओं के लिए कम रिक्तियों के कारण जेएजी विभाग के लिए चयन नहीं किया। अधिकारियों ने पुरुषों और महिलाओं के लिए असमान रिक्तियों को चुनौती दी और कहा कि कुल 6 पदों में से केवल तीन महिलाओं के लिए होने के कारण उनका चयन नहीं हो सका। पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा, प्रथम दृष्टया हम याचिकाकर्ता- 1 अर्शनूर कौर द्वारा स्थापित मामले से संतुष्ट हैं। शीर्ष अदालत ने आगे कहा, तदनुसार, हम प्रतिवादियों को जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) के रूप में नियुक्ति के लिए अगले

उपलब्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उनके प्रवेश के उद्देश्य से आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देते हैं।

पीठ ने एक अखबार के लेख का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि एक महिला लड़ाकू पायलट राफेल विमान उड़ाएगी और ऐसी स्थिति में उसे युद्धबंदी बनाया जा सकता है। न्यायमूर्ति दत्ता ने केंद्र और सेना की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा, अगर भारतीय वायुसेना में एक महिला के लिए राफेल लड़ाकू विमान उड़ाना जायज़ है, तो सेना के लिए जेएजी में ज्यादा महिलाओं को अनुमति देना इतना मुश्किल क्यों है?

पीठ को सूचित किया गया कि दूसरी याचिकाकर्ता त्यागी कार्यवाही के दौरान भारतीय नौसेना में शामिल हो गई हैं। शीर्ष अदालत ने तब केंद्र से लिंग-तटस्थ पदों का दावा करने के बावजूद महिलाओं के लिए कम पद आरक्षित करने पर सवाल उठाया। सेना की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया कि सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती और रोजगार, जिसमें जेएजी शाखा भी शामिल है, उसकी परिचालन तैयारियों को ध्यान में रखते हुए एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, 2012 से 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के अधिकारियों की 70ः30 (या अब 50ः50) के अनुपात में भर्ती की नीति को भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कहना न केवल गलत होगा, बल्कि कार्यपालिका के क्षेत्र में भी अतिक्रमण होगा, जो भारतीय सेना में पुरुषों और महिलाओं के अधिकारियों की भर्ती का निर्णय लेने के लिए एकमात्र सक्षम और एकमात्र प्राधिकारी है। शीर्ष अदालत ने आगे पूछा कि पदों को लिंग-तटस्थ क्यों कहा गया जब उच्च योग्यता वाली महिला उम्मीदवार रिक्तियों को अभी भी लिंग के आधार पर विभाजित किए जाने के कारण योग्य नहीं थीं। जस्टिस मनमोहन ने टिप्पणी की कि यदि 10 महिलाएं योग्यता के आधार पर जेएजी के लिए योग्य होती हैं तो क्या उन सभी को जेएजी शाखा में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। न्यायाधीश ने कहा कि लिंग तटस्थता का अर्थ 50ः50 प्रतिशत नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस लिंग का है।

भाटी ने केंद्र के फैसले का बचाव किया और कहा कि जनशक्ति मूल्यांकन और आवश्यकता के आधार पर सेना की सभी शाखाओं में लिंग-विशिष्ट रिक्तियां मौजूद थीं। उन्होंने कहा, जेएजी शाखा के कामकाज को शांति काल के दौरान सैन्य कमांडरों के मात्र कानूनी सलाहकारों के रूप में अलग-थलग नहीं देखा जा सकता है। यह भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग है और इसकी परिचालन तैयारियों में भी इसकी समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। भाटी ने आगे कहा कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग एसएसबी आयोजित करना शामिल परीक्षणों की प्रकृति के कारण एक आवश्यकता है, जिसमें घनिष्ठ गहन शारीरिक संपर्क की आवश्यकता होती है। भाटी ने रक्षा सेवाओं में लैंगिक एकीकरण के पहलू को एक विकसित प्रक्रिया बताया, जो परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप और समय-समय पर समीक्षा और अध्ययनों के अधीन है। उन्होंने कहा, भर्ती नीतियां 2024 से 70ः30 के अनुपात से बढ़कर 50ः50 हो गई हैं। यह कैडर स्वास्थ्य और तैनाती प्रतिबंधों के अनुरूप है, जो मनमाना नहीं है। परिचालन अनिवार्यताओं को ध्यान में रखे बिना समानता या तटस्थता का कोई भी न्यायिक अधिरोपण सेना की कमान और नियंत्रण और परिचालन तैयारियों दोनों को कमजोर कर सकता है।

इससे पहले, जब शीर्ष अदालत ने पूछा था कि जेएजी महिला अधिकारियों को केवल खतरे की आशंका के कारण युद्ध क्षेत्रों में क्यों तैनात नहीं किया जाता है, तो भाटी ने इसे भारत सरकार द्वारा महिला अधिकारियों को अग्रिम पंक्ति की युद्ध तैनाती में तैनात होने से रोकने के लिए सचेत निर्णय बताया था, जिससे वे दुश्मन के संपर्क में आने के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं।

बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ने वाली महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार

-दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

नईदिल्ली,एंजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक महिला का अपने बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ना %स्वैच्छिक परित्याग' नहीं होता है, इसलिए वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 13 मई को जारी एक आदेश में कहा कि इस स्थिति को बच्चे की देखभाल करने के परम कर्तव्य के परिणाम के तौर पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक महिला और उसके नाबालिग बेटे को अंतरिम भरण-पोषण देने संबंधी निचली अदालत के आदेश को खारिज करने से मना कर दिया।

महिला के पति ने निचली अदालत के अक्टूबर 2023 के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उसे (पति को) अलग रह रही अपनी पत्नी और बच्चे को 7,500 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता पति को निर्देश दिया कि वह महिला को निचली अदालत द्वारा निर्धारित मासिक राशि देना जारी रखे, साथ ही अपने बच्चे के लिए अलग से प्रतिमाह 4,500 रुपये दे। कोर्ट ने कहा, %%यह पूरी तरह से स्थापित तथ्य है कि नाबालिग बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी माता या पिता पर असमान रूप से पड़ती है, जो अक्सर पूर्णकालिक रोजगार की उनकी क्षमता को सीमित कर देती है, खासकर उन मामलों में जहां मां के नौकरी पर होने के दौरान उसके बच्चे की देखभाल में परिवार का कोई सहयोग नहीं मिलता है।''

फैसले में कहा गया है कि महिला द्वारा रोजगार छोड़ने को %%काम का स्वैच्छिक परित्याग'' नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे बच्चे की देखभाल के परम कर्तव्य के परिणामस्वरूप जरूरी माना जाता है। व्यक्ति ने निचली अदालत के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि महिला उच्च शिक्षा प्राप्त थी और पहले दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर के रूप में काम करती थी, जिससे वह प्रतिमाह ट्यूशन फीस सहित 40,000 से 50,000 रुपये कमाती थी। पति ने दावा किया था कि महिला कमाने और खुद का तथा बच्चे का भरण-पोषण करने में सक्षम थी, लेकिन उसे (पति को) परेशान करने के इरादे से याचिका दायर की गई।

अपीलकर्ता ने दलील दी थी कि फैमिली कोर्ट ने इस तथ्य पर विचार न करके त्रुटि की है कि महिला अपनी मर्जी से ससुराल से चली गई थी और अदालत के आदेश के बावजूद उसने अपने पति के साथ अपने वैवाहिक संबंध फिर से शुरू नहीं किए। पति ने दावा किया कि वह अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे के साथ रहने को तैयार है। उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि वह हरियाणा में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है और प्रतिमाह केवल 10,000 से 15,000 रुपये ही कमाता है, इसलिए वह अंतरिम भरण-पोषण संबंधी निचली अदालत के आदेश का पालन करने में असमर्थ है।

दूसरी ओर, महिला ने दलील दी कि वह बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के कारण काम करने में असमर्थ थी। उसने कहा कि उसका पिछला रोजगार उसे उचित भरण-पोषण से वंचित करने का वैध आधार नहीं है। उसने दलील दी कि चूंकि उसे आने-जाने में बहुत समय लगता था और उसे घर के पास काम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसने अपना टीचिंग करियर छोड़ दिया। अदालत ने महिला की दलील स्वीकार कर ली और उसके स्पष्टीकरण को %%तार्किक और न्यायोचित'' पाया। बेंच ने कहा कि व्यक्ति का आय प्रमाण-पत्र रिकॉर्ड में नहीं है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि वह अंतरिम भरण-पोषण की अर्जी तथा अंतरिम अवधि में व्यवस्था जारी रखने के लिए नए सिरे से निर्णय ले।

अखिलेश यादव ने मिलिट्री स्कूलों की स्थापना की उठाई मांग, भारतीय सेना की बहादुरी की सराहना

लखनऊ,एंजेंसी लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय के डॉ राममनोहर लोहिया सभागार में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय सेना की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय सेना न केवल सबसे मजबूत और सशक्त है, बल्कि इसकी वीरता पर हम सभी को गर्व है।अखिलेश यादव ने इस अवसर पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के योगदान को भी सराहा और कहा कि यह परंपरा देश की आज़ादी से लेकर अब तक निरंतर जारी रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मिलिट्री स्कूलों की आवश्यकता है, जहां से सच्चे देशप्रेमियों का निर्माण हो सके।उन्होंने अपनी मांग को दोहराया कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सहारनपुर, कन्नौज, इटावा, वाराणसी, और संत कबीरनगर जिलों में नए मिलिट्री स्कूल खोले जाएं ताकि देश की अखंडता और एकता को चुनौती देने वाली ताकतों को निर्णायक जवाब दिया जा सके।अखिलेश यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की सुरक्षा की संवेदनशील परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार करेगी और जल्द ही मिलिट्री स्कूलों की स्थापना की घोषणा करेगी।अखिलेश यादव ने कहा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में अध्ययन के दौरान उन्हें देशभक्ति, अनुशासन और पराक्रम का प्रेरणास्त्रोत मिला।

जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने किया निर्माणाधीन वृद्धाश्रम का स्थलीय निरीक्षण

इंडिया वार्ता ब्यूरो

अल्मोड़ा । जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का गहन अवलोकन किया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण एजेंसी को निर्देशित किया कि कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा मानकों के अनुरूप ही कार्य पूर्ण किया जाए। जिलाधिकारी ने वृद्धाश्रम से जुड़ी सड़क के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने सड़क कटाव में पाई गई कमियों की ओर इशारा करते हुए इन्हें शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सड़क न केवल वृद्धाश्रम के लिए, बल्कि समीपवर्ती दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यरत मंगलदीप विद्यालय की नई निर्माणाधीन इमारत के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्यों को शीघ्रता से एवं तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए, ताकि वृद्धजनों को शीघ्र सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम का निर्माण जनपद अल्मोड़ा के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक परियोजना है, जिसका लाभ बुजुर्गों को दीर्घकालिक रूप से मिलेगा।

निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी, उपजिलाधिकारी संजय कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी आराधना त्रिपाठी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता उपस्थित रहे।

भारतीय सेना के आगे धरे रह गये पाक के न्यूक्लियर वेपन्सः महाराज

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून। । प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण,पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि भारतीय सेना ने आपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के ठिकानों को चुन-चुनकर तबाह कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एयर बेस और आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में नाविक उपग्रह की भी अति महत्वपूर्ण भूमिका रही है।उन्होंने बताया कि नाविक उपग्रह एक स्वदेशी नौवहन उपग्रह प्रणाली (आईआरएनएसएस) है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने विकसित किया है। यह नेविगेशन, समय निर्धारण और स्थिति निर्धारण सेवाएं प्रदान करता है। यह अमेरिका के जीपीएस (की तरह ही काम करता है।नाविक का उपयोग स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, वाहन ट्रैकिंग और अन्य कई अनुप्रयोगों में किया जाता है। नाविक सैटेलाइट का एक नमूना मसूरी स्थित जार्ज एवरेस्ट के संग्रहालय में भी रखा गया है। महाराज ने कहा कि इस आपरेशन में हमारी सेना की बहादुरी, कौशल और समर्पण ने एक बार फिर देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। उन्होंने आपरेशन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसएए अजित डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, नौ सेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी.सिंह, भारतीय सेना सभी अधिकारियों और सेना की भूमिका की सराहना करते हुए बधाई दी है।उन्होंने कहा कि आपरेशन सिंदूर की सफलता ने दिखा दिया है कि हमारी सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और वह देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। भारतीय सेना की इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और देश की जनता को गर्व महसूस कराया है। आपरेशन सिंदूर की सफलता में भारतीय वीरांगना कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी महिला अधिकारियों की भूमिका भी अति महत्वपूर्ण रही है, जिन्होंने अपनी बहादुरी, कौशल और सूझबूझ से इस आपरेशन को अंजाम दिया है। पाकिस्तान द्वारा शुरू किए गए इस अघोषित युद्ध के पश्चात निश्चित रूप से भारत की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है और भारत विश्व की एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। महाराज ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा भारत पर बार-बार न्यूक्लियर हमले की गीदड़ भपकी देने वाले पाकिस्तान के नूरखान एयर बेस पर भारतीय सेना के हमले के बाद उसके न्यूक्लियर वेपन्स धरे के धरे रह गये हैं। बताया तो यहां तक भी जा रहा है कि पाकिस्तान के किराना हिल्स पर स्थित उसके न्यूक्लियर वेपन्स भी भारतीय हमले की जद में आये हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत में जिस प्रकार की कार्यवाही करते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी व सैन्य ठिकानों को तबाह किया उससे न केवल विश्व को भारत की ताकत का पता चला है बल्कि पाकिस्तान को भी घुटने टेकने पर विवश होना पड़ा है।

यातायात नियम तोड़ने पर 165 डिलीवरी ब्वॉयज के चालान

देहरादून । यातायात नियम तोड़कर सामान और फूड की डिलीवरी करने वाले डिलीवरी ब्वॉय के खिलाफ मंगलवार शाम से देर रात पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों को उल्लंघन करने पर 165 डिलीवरी ब्वॉय के मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किए गए। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि डिलीवरी ब्वॉय के कई बार संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहने की शिकायत आती है। इसके बाद जिले में सभी थानों की पुलिस इनके सत्यापन का निर्देश दिया गया।

मई माह में आयोजित होंगे विभिन्न जन-जागरुकता अभियान

अल्मोड़ा (इंडिया वार्ता ब्यूरो)। माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा श्री श्रीकांत पाण्डेय जी के मार्गदर्शन में सुश्री शचि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा के निर्देशन में जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों, स्कूलों, कालेजों आदि में आज दिनांक 14 मई 2025 से बाल विवाह मुक्त उत्तराखण्ड तीन दिवसीय जागरुकता अभियान, दिनांक 17 व 18 मई 2025 को बाल श्रम मुक्त उत्तराखण्ड दो दिवसीय जागरुकता अभियान, दिनांक 19 व 20 मई 2025 को उड़ान- शोषण से स्वतंत्रता दो दिवसीय जागरुकता अभियान, दिनांक 21 व 22 मई 2025 को नालसा (बच्चों के लिए बाल अनुकूल सेवाएं)योजना 2024 एवं नालसा (मानसिक रुप से विक्लांग व्यक्तियों और बौद्धिक रुप से विक्लांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना 2024 के अंतर्गत दो दिवसीय जागरुकता अभियान, दिनांक 23 व 24 को सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा दो दिवसीय जागरुकता अभियान,दिनांक 25 व 26 मई 2025 को सुरक्षित दवा-सुरक्षित जीवन दो दिवसीय जागरुकता अभियान व दिनांक 31 मई 2025 को तम्बाकू मुक्त देवभूमि उत्तराखण्ड एक दिवसीय जागरुकता अभियान चलाया जायेगा जिसमें उपरोक्त विषयों के संबंध में जागरूकता शिविर, रैली, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जायेगा।

श्रद्धालुओं की हृदय गति रूकने से मौत, तीन तक पहुंचा मृतकों का आंकड़ा

उत्तरकाशी,इंडिया वार्ता ब्यूरो। यमुनोत्री धाम की यात्रा के दौरान जानकीचट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग भैरव मंदिर के पास एक श्रद्धालु की हृदय गति रूकने से मौत हो गई। यमुनोत्री धाम में 15 दिनों में यह तीसरी मौत हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार दंतपुरा मुरैना मध्य प्रदेश के 60 वर्षीय राजेन्द्र कुमार परिजनों के साथ यमुनोत्री धाम मां यमुना के दर्शन करने जा रहे थे। भैरव मंदिर के पास अचानक तबीयत बिगड़ी उन्हें पुलिस जवानों की मदद से जानकीचट्टी चिकित्सालय लाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही श्रद्धालु ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर हरदेव सिंह पंवार के अनुसार उनकी श्रद्धालु की मौत हार्टअटैक से हुई है। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर इससे पहले दो मौतें हो चुकी है।

कृति खरबंदा ने पिंक लुक में ढाया कहर, सोशल मीडिया पर मची हलचल

कृति खरबंदा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर गुलाबी साड़ी में कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें साझा कीं, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। एक्ट्रेस हर अंदाज़ में बेहद ग्रेसफुल और एलिगेंट नज़र आईं, और उनकी दिल को छू लेने वाली कैप्शन ने इस पल को और भी खास बना दिया-

फैंस ने उनकी तारीफों की बाढ़ ला दी, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा उनके पति पुलकित सम्राट के प्यारे से कमेंट ने—प्रिटी खरबंदा।

इस सिंपल लेकिन दिल छू लेने वाले कमेंट ने फैंस का दिल जीत लिया और सभी उनकी बॉन्डिंग की तारीफ करने लगे।

मार्च 2024 में शादी के बंधन में बंधे ये कपल हाल ही में अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी मना चुका है। प्यार, हँसी और एक-दूसरे के प्रोफेशनल सफर में दिए गए सपोर्ट से भरा उनका एक साल बेहद खास रहा है। चाहे इवेंट्स में एक-दूसरे को सपोर्ट करना हो या सोशल मीडिया पर कैंडिड मोमेंट्स शेयर करना—कृति और पुलकित आज बॉलीवुड के सबसे क्यूट और पसंदीदा कपल्स में गिने जाते हैं।

उनकी लव स्टोरी आज भी दिलों को जीत रही है, और फैंस उनके ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री के दीवाने हैं।

संत रामपाल महाराज का हल्द्वानी में आश्रम सील

हल्द्वानी , इंडिया वार्ता ब्यूरो। हरियाणा के चर्चित संत रामपाल महाराज के हल्द्वानी स्थित संतलोक आश्रम को सील कर दिया गया है। बिल्डिंग बॉयलाज के उल्लंघन पर बुधवार को जिला विकास प्राधिकरण की टीम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। मामले में विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव के न्यायालय से सात मई को आश्रम को सील करने का आदेश जारी किया गया था। डहरिया क्षेत्र के लोगों की शिकायत पर प्राधिकरण ने 11 अप्रैल को धान मिल रोड स्थित मॉल के समीप बने संतलोक आश्रम का निरीक्षण किया था। सामने आया कि क्षेत्र में आवासीय भवन के लिए मानचित्र पास कराया गया था।

फ्यूचर जेनेराली ने 'हैल्थ अनलिमिटेड' लॉन्च किया

देहरादून, इंडिया वार्ता ब्यूरो। भारत के शहरों में रहने वाले बहुत से लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कराना खुद को वित्तीय रूप से सुरक्षित करने का एक समाधान है, लेकिन अस्पताल में भर्ती व इलाज की बढ़ती लागत के मद्देजर यह सवाल उठता है कि हमारा स्वास्थ्य बीमा कवर पर्याप्त है या नहीं। यह बढ़ती चिंता इस पहलू पर प्रकाश डालती है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव हैल्थकेयर समाधानों की कितनी आवश्यकता है। फ्यूचर जेनेराली इंडिया इंश्योरेंस द्वारा किए गए ऐक्सक्लूसिव सर्वे – हैल्थ अनलिमिटेड में पता लगा है कि हर दस में से आठ से अधिक लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य बीमा कवर पर्याप्त है या नहीं। यह सर्वेक्षण हाल ही में 25 से अधिक उम्र के 800 लोगों पर किया गया जिन्होंने हैल्थ इंश्योरेंस ले रखा था और इसमें उन लोगों की वर्तमान स्वास्थ्य बीमा कवरेज की पर्याप्तता के बारे में बढ़ती चिंताओं का पता चला। **2021** में एशिया में सबसे ज्यादा मेडिकल इन्फ्लेशन भारत में था– लगभग 14 प्रतिशत। जबकि उस साल अन्य एशियाई देशों में यह आंकड़ा इस प्रकार था– चीन: 12 प्रतिशत, इंडोनेशिया: 10 प्रतिशत, वियतनाम: 10 प्रतिशत और फिलीपींस: 9 प्रतिशत। हैल्थ अनलिमिटेड के लॉन्च पर फ्यूचर जेनेराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ अनुप राऊ ने कहा, ''चिकित्सा उपचार की बढ़ती लागत भारत में बहुत से लोगों के लिए चिंता का कारण है, और यह चिंता स्वास्थ्य बीमा कराने के बावजूद है। हम अपने ग्राहकों के लाइफटाइम पार्टनर के तौर पर यह प्रयास करते हैं कि इन चुनौतियों का समाधान मुहैया कराया जाए, इसलिए हम अपने भारतीय ग्राहकों को उनके मुताबिक समाधान बना कर पेश करते हैं ताकि उन्हें पर्याप्त कवर प्राप्त हो सके। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव हैल्थ इंश्योरेंस पेशकश 'हैल्थ अनलिमिटेड' यह सुनिश्चित करेगी कि अगर कभी हमारे ग्राहकों को बहुत ज्यादा बिल का सामना करना पड़े तब भी उनका कवर बरकरार रहे, फिर चाहे उनका सम इंश्योर्ड समाप्त ही क्यों न हो चुका हो।''

सम इंश्योर्ड के अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का यह क्रांतिकारी प्लान दूसरे क्लेम से शुरू होगा और कवरेज खत्म होने की चिंता के बिना पूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। बेस कवरेज के अतिरिक्त यह प्लान बढ़ती चिकित्सा लागत और उभरती हैल्थकेयर जरूरतों से सुरक्षा प्रदान करता है। अस्पताल में भर्ती से पहले-दौरान-बाद में होने वाले खर्चे, डे-केयर ट्रीटमेंट, आयुष उपचार (पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध व होम्योपैथी), अंग दान की लागत तथा आधुनिक उपचार विधियां – ये सभी इस प्लान में कवर किए जाते हैं।

दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में कासीगा स्कूल के छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन

देहरादून, इंडिया वार्ता ब्यूरो। कासीगा स्कूल,देहरादून के छात्रों ने प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दसवीं तथा बारहवीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। कासीगा स्कूल, देहरादून ने एक बार फिर से अकादमिक वर्ष 2024-25 के सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में अपनी असाधारण शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं दोनों में 100 प्रतिशत परिणाम प्राप्त किया है। बारहवीं कक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए मन्नत गर्ग ने 96 प्रतिशत, ध्रुव सूर्येवाला ने 94.3 प्रतिशत, चंद्रहास प्रताप सिंह ने 92.8 प्रतिशत, हर्षिद माडम ने 91.8 प्रतिशत, मैथिली अरोड़ा और कृष अग्रवाल ने 91 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। दसवीं कक्षा में युक्ता मंडल ने 96.2 प्रतिशत, विराट मोदी ने 94.2 प्रतिशत और डॉली बगांग ने 94 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। वत्सल सक्सेना, यथार्थ यादव और यश अग्रवाल ने भी क्रमश: 93.6 प्रतिशत, 92.8 प्रतिशत और 91.2 प्रतिशत अंक हासिल किए। ऋषभ डागर और ध्रुव अग्रवाल ने भी अपनी उत्कृष्टता का परिचय देते हुए 91 प्रतिशत अंक अर्जित किए। कासीगा स्कूल छात्रों के लिए प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है, जो उन्हें विविध शिक्षण अवसर प्रदान करता है और समग्र विकास के साथ व्यक्तिगत प्रगति को प्रोत्साहित करता है । यह उपलब्धि स्कूल को एक नई ऊंचाई की ओर रेखांकित करती है, जो छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और दूरदर्शी नेतृत्व के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है। कासीगा परिवार के सभी सदस्यों को उनकी मेहनत और समर्पण के लिए हार्दिक बधाई। कासीगा स्कूल-प्रबंधन तथा शिक्षकों की ओर से छात्रों की उत्कृष्ट सफलता के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

एचडीएफसी बैंक यूपी और उत्तराखंड में राइड इनटू जॉय टू-व्हीलर लोन कार्निवल लेकर आया

देहरादून, इंडिया वार्ता ब्यूरो। भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राइड इनटू जॉय टू-व्हीलर लोन कार्निवल का उद्घाटन करने की तैयारी कर ली है। यह टू-व्हीलर लोन मेला 15-16 मई, 2025 को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बैंक की 550 शाखाओं में आयोजित किया जाएगा। क्षेत्र के प्रमुख टू-व्हीलर डीलरशिप नवीनतम टू-व्हीलर पेशकशों का प्रदर्शन करेंगे। इस पहल का उद्देश्य टू-व्हीलर फाइनेंस तक आसान पहुँच प्रदान करना है, साथ ही खरीदारों को वास्तविक टू-व्हीलर डीलरों से जोड़ने के लिए एक अनूठा प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध करवाना है। इस पहल से ग्राहकों को नवीनतम दोपहिया मॉडल ब्राउज़ करने, टेस्ट ड्राइव करने और मौके पर ही ऋण स्वीकृत करवाने (पात्र बैंक ग्राहकों के लिए) का अवसर मिलेगा, जिसमें उपयुक्त पुनर्भुगतान विन्यास और न्यूनतम कागजी कार्रवाई की सुविधा शामिल होगी। एचडीएफसी बैंक के शाखा बैंकिंग प्रमुख (उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) मुस्कान सिंह ने कहा दोपहिया वाहन ऋण कार्निवल लोगों को वाहन खरीदने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। बैंक ने राज्य में बड़ी संख्या में नई शाखाएँ खोली हैं, जो हमारे दोपहिया वाहन ऋण प्रस्तावों को ग्राहकों को उनके घर के नज़दीकी दायरे में उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

घोषणाओं का अंबार नतीजा शून्य : गरिमा दसौनी

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड में विकास कार्यों की घोषणाओं का अंबार तो लगा है, लेकिन धरातल पर स्थिति बिलकुल विपरीत है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में 卐अंधेर नगरी चौपट राजा卐 जैसा माहौल बन गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 348 अधूरी विकास योजनाओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया।

बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में उत्तराखण्ड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा की गई 723 घोषणाओं में से 338 आज भी अधूरी हैं। यह जानकारी मुख्य सचिव आनंद वर्धन की समीक्षा बैठक में सामने आई है। उन्होंने बताया कि युवा कल्याण, वन एवं पर्यावरण, धर्मस्व, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों में 50त्न से अधिक घोषणाएं अधूरी पड़ी हैं।

गरिमा दसौनी ने आंकड़ों के साथ स्पष्ट किया कि जुलाई 2021 से अब तक मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं में युवा कल्याण विभाग में सबसे अधिक 78त्न घोषणाएं अधूरी हैं। इसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 61त्न, वन एवं पर्यावरण विभाग में 58त्न, खेल विभाग में 44त्न और समाज कल्याण में 31त्न घोषणाओं को पूरा किया जाना शेष है। धर्मस्व विभाग में 51त्न घोषणाएं अधूरी हैं, जबकि पेयजल विभाग में 26त्न घोषणाओं पर अभी काम चल रहा है।

उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को लंबित घोषणाओं को तेजी से पूरा करने और अव्यवहारिक घोषणाओं को रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, अधिक धनराशि वाली योजनाओं के लिए बाहरी सहायता से बजट जुटाने को कहा गया है।

कांग्रेसी प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के अंतिम चरण में, अधिकारी कैसे तय करेंगे कि कौन सी घोषणा व्यावहारिक है और किसे रद्द किया जाना चाहिए? उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए घोषणाएं करते हैं, और बाद में अधिकारी उन्हें रद्द कर देते हैं। उन्होंने पूछा कि जब घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई हैं, तो अधिकारी उन पर फैसला कैसे ले सकते हैं?

उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर ही अमल नहीं हो रहा है, तो आम जनता और विपक्ष की सुनवाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह मुख्यमंत्री के अधिकारियों पर नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

पटेलनगर चोरी कांड का पर्दाफाश, शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी के मोबाइल बरामद

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून। दून पुलिस ने पटेलनगर क्षेत्र में कुछ दिन पहले हुई चोरी की घटना का सफलता पूर्वक अनावरण कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से चोरी किए गए दो मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। पटेलनगर कोतवाली में दिनांक 12 मई 2025 को सपनिल रावत, निवासी बहुगुणा कॉलोनी कारगी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 5 मई की रात को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर में घुसकर दो मोबाइल फोन - मोटोरोला और सैमसंग कंपनी के - चोरी कर लिए हैं। इस शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पटेलनगर कोतवाली में **मु0अ0सं0-210/2025** धारा-**305(A)**/331(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पटेलनगर ने एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया। इस टीम ने घटनास्थल के आसपास और आने-जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और संदिग्ध व्यक्ति की पहचान के लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। आज, दिनांक 14 मई **2025** को पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर, पुलिस टीम ने वेद सिटी जाने वाले कच्चे रास्ते से चोरी में शामिल अभियुक्त सत्यम उर्फ चिरवा पुत्र राम कृपाल, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम कोहनिमा, थाना बलरामपुर, जनपद गोंडा, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किए गए दोनों मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। पूछताछ के दौरान, अभियुक्त सत्यम ने कबूल किया कि उसने ही रात्रि के समय बहुगुणा कॉलोनी कारगी में एक घर के अंदर घुसकर इन मोबाइल फोनों को चुराया था। इस सराहनीय कार्य को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में महिला उपनिरीक्षक मीना रावत, कांस्टेबल विपिन कुमार और कांस्टेबल अरविंद बर्त्वाल शामिल थे। दून पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के प्रति विश्वास बढ़ा है।

मेरे खिलाफ रची जा रही साजिश, हो रहा नैरेटिव तैयार: रणजीत सिंह रावत

नैनीताल, इंडिया वार्ता ब्यूरो। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को लेकर चल रहा विवाद अपने चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने यह आरोप लगाया कि उनके खिलाफ पार्टी के सुपारी किलर की ओर से सुनियोजित साजिश रची जा रही है। जिसके लिए खास नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीते दिनों जो घटना हुई, उसके बाद कुछ तथाकथित पार्टी के ही कुछ लोग सुपारी किलर से मिलकर उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। जो लोग खुद अवैध शराब, जुआ, सट्टा और वसूली में लिप्त है, वो आज मेरे खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहे हैं। रणजीत रावत ने आरोप लगाया कि वो रामनगर का माहौल बिगाड़ रहे हैं। उनका कहना है कि गैंग से जुड़कर ये लोग न सिर्फ अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। बल्कि, कालाढूंगी कांड के मुख्य जनक भी हैं। रामनगर के कई घरों की चिराग बुझाने वाले लोग हैं। अब ये राजनीतिक संरक्षण पाकर व्यापारियों और आम जनता में भय फैलाने का काम कर रहे हैं। पूर्व विधायक रणजीत रावत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यालय पर कब्जे की कार्रवाई पूरी तरह एकतरफा थी। पुलिस प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के जबरन कब्जा करवा दिया।

मुख्यमंत्री ने दी विभिन्न विकास योजनाओं की स्वीकृति

देहरादून, इंडिया वार्ता ब्यूरो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद पिथौरागढ़ में बरड़ बैंड से पांखू कोकिला देवी मंदिर तथा पांखू से धरम घर होते हुए कोटमनिया तक सडक सुधारीकरण व डामरीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पूर्व में मसूरी स्थित शहीद स्थल पर शेड के निर्माण किये जाने की घोषणा को मसूरी शहीद स्मारक समिति द्वारा किये गये अनुरोध पर संशोधित करते हुए मसूरी शहीद स्थल से लगी भूमि पर उत्तराखण्ड आंदोलन में शहीदों के नाम पर संग्रहालय बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए प्रदान की वित्तीय स्वीकृति। मुख्यमंत्री ने जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में ग्राम पंचायत पीतना में बहुउद्देशीय भवन के निर्माण किये जाने हेतु 95.84 लाख तथा गांधी इंटर कॉलेज पनुआनौला में 04 कक्षों के निर्माण किये जाने हेतु 99.95 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनियन वेलनेस डिपॉजिट का किया शुभारंभ

देहरादून, इंडिया वार्ता ब्यूरो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में खुदरा ग्राहकों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई, अपनी नई और नवोन्मेषी अवधि जमा योजना यूनियन वेलनेस डिपॉजिट का शुभारंभ किया गया। यूनियन वेलनेस डिपॉजिट को अवधि जमा उत्पाद के साथ स्वास्थ्य बीमा को सहजता से एकीकृत करके धनर्जन और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसके अतिरिक्त, यह रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड के माध्यम से कई प्रकार के जीवनशैली लाभ प्रदान करता है. यह योजना 18 से 75 वर्ष की आयु के निवासी व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से उपलब्ध है. संयुक्त खातों के लिए, केवल प्राथमिक खाताधारक ही बीमा कवरेज के लिए पात्र होंगे। इसमें न्यूनतम जमा राशि घ्10.00 लाख और अधिकतम घ्3 करोड़ है, जिसमें समय से पहले बंद करने और जमा पर ऋण की सुविधा है. इस योजना की अवधि 375 दिन है और यह 6.75: प्रति वर्ष की आकर्षक ब्याज दर प्रदान करती है, साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए 0.50: अतिरिक्त ब्याज भी प्रदान करती है। इस उत्पाद की एक विशिष्टता 375-दिन के सुपर टॉप-अप स्वास्थ्य बीमा कवर का समावेशन है, जो कैशलेस अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा के साथ घ्5.00 लाख की बीमा राशि प्रदान करता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक संदीप शर्मा ने इंडिया प्रिन्टर शांप न. 06 संगम प्लाजा धर्मपुर देहरादून से मुद्रित करवाकर मोहक्कमपुर खुर्द पोस्ट आई.आई.पी. रेलवे क्रसिंग हरिद्वार रोड़ देहरादून (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया।

प्रधान सम्पादक : संजीव शर्मा

संपादकः संदीप शर्मा

सह सम्पादक : डा. विष्णु बिश्वास

संजीव अग्निहोत्री गढ़वाल प्रभारी

अल्मोड़ा जिला प्रभारी : रोहित कार्की

अल्मोड़ा संवाददाता : रक्षित कार्की

ब्यूरो चीफ : राजीव अग्रवाल

Email.
indiawarta@gmail.com
indiawarta@rediffmail.com
Web Site
www.indiawarta.com
R.N.I NO. UTTHIN/2011/39104
M- 7500471414,7500581414

नोट& समाचार पत्र में सभी पद अवैतानिक हैं। किसी भी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा।
R.N.I NO. UTTHIN/2011/39104

मुख्य सचिव ने हरिद्वार कॉरिडोर, ऋषिकेश मास्टर प्लान और शारदा कॉरिडोर के सम्बन्ध में बैठक ली

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून। मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें हरिद्वार कॉरिडोर, ऋषिकेश मास्टर प्लान और शारदा कॉरिडोर से संबंधित विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। उत्तराखंड निवेश एवं अवसंरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) ने इस अवसर पर इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव श्री बर्द्धन ने हरिद्वार कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले सभी विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं को जल्द से जल्द जमीन पर उतारना संभव है, उन पर प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू किया जाए।

हरिद्वार के धार्मिक महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यह न केवल भारत बल्कि विदेशों में बसे करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कॉरिडोर के विकास कार्यों के दौरान आस्था से जुड़े क्षेत्रों और उनके मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने योजनाओं से जुड़े सभी हितधारकों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने का भी आह्वान किया। श्री बर्द्धन ने यूआईआईडीबी को हरिद्वार कॉरिडोर के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के लिए बजट, कार्यदायी संस्था और रखरखाव सहित एक समग्र योजना शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक परियोजना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों को योजना में शामिल किया जाए।

हरिद्वार कॉरिडोर के विशिष्ट प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने ब्रह्मकुंड और महिला घाट के क्षेत्रों का विस्तार करने के निर्देश दिए। सती कुंड के पुनर्विकास कार्य में उन्होंने इसके ऐतिहासिक महत्व और मूल थीम को बनाए रखने की बात कही। हरिद्वार में मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण के दौरान नदी के मनोरम दृश्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो चुकी है, उन पर आगे की कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए। शारदा नदी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के कार्यों की प्राथमिकता भी मुख्य सचिव द्वारा निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कार्यों की प्रकृति के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा ही उन्हें पूरा किया जाए। वन भूमि में ईको टूरिज्म गतिविधियों को शामिल करने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। श्री बर्द्धन ने यूआईआईडीबी को जिलाधिकारी चंपावत द्वारा प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को भी शारदा कॉरिडोर में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना में टूरिज्म सर्किट के विकास के साथ-साथ कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए हेलीपैड और हेलीपोर्ट के प्रावधान रखने की आवश्यकता बताई।

ऋषिकेश मास्टर प्लान पर चर्चा के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ऋषिकेश के मोबिलिटी प्लान और पुराने रेलवे स्टेशन के आसपास प्रस्तावित कार्यों को समग्र रूप से तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने चंद्रभागा नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए हाइड्रोलॉजी सर्वे कराने की बात भी कही। अंत में, मुख्य सचिव ने सभी परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करते हुए अत्यंत आवश्यक कार्यों को तत्काल शुरू करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने हरिद्वार कॉरिडोर, शारदा रिवरफ्रंट डेवलपमेंट और ऋषिकेश मास्टर प्लान के कार्यों के महत्व को देखते हुए तेजी से कार्रवाई शुरू करने का आह्वान किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव श्री नितेश कुमार झा, श्री सचिन कुर्वे, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. वी. षणमुगम और मुख्य वन संरक्षक श्री पी.के. पात्रो सहित अन्य संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे।

सेना के अपमान पर भड़के कांग्रेस नेता, मंत्री को बर्खास्त करने की मांग

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा देश की सेना के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल मंत्री को बर्खास्त करने और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग की है।

धस्माना ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनकी तीसरी पीढ़ी सेना में है, और विंग कमांडर व्योहमिका सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जानकारी देश को दी थी। इन दोनों अधिकारियों का देश के प्रति योगदान अतुलनीय है, और मंत्री द्वारा उन पर की गई टिप्पणी शर्मनाक और देशद्रोह की श्रेणी में आती है।

उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद भारतीय सैन्य बलों ने जिस साहस का परिचय दिया, और पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, उसकी जानकारी इन अधिकारियों ने ही देश को दी थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी युद्धविराम की जानकारी दी थी, जिसके बाद कट्टरपंथी भाजपा समर्थकों ने उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया। धस्माना ने कहा कि यह स्पष्ट है कि ट्रंप के दखल के बाद भाजपा अपने नफरती एजेंडे पर लौट आई है।

उन्होंने 卐तिरंगा शौर्य यात्रा卐 को केवल वोटों की राजनीति करार दिया। धस्माना ने कहा कि जब देश इन अधिकारियों का सम्मान कर रहा है, तब भाजपा नेता उनका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की चुप्पी से स्पष्ट है कि वह ऐसे कृत्यों का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए।

प्रेस वार्ता में प्रदेश श्रम प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिनेश कौशल भी उपस्थित थे।

उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री से भेट की

देहरादून, इंडिया वार्ता ब्यूरो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निवास पर आज एक महत्वपूर्ण सौजन्य भेंट हुई। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य समन्वयक और प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि और पूर्व राज्य मंत्री अजय सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस भेंट में, उन्होंने राज्य के जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

सूत्रों के अनुसार, यह मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसमें राज्य के विकास और जनता की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इस भेंट के बारे में राजीव महर्षि ने कहा, यह एक सौजन्य भेंट थी, जिसमें हमने राज्य के विकास और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। हम मुख्यमंत्री के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पूर्व राज्य मंत्री अजय सिंह ने भी इस भेंट को सकारात्मक बताया और कहा, मुख्यमंत्री ने हमारी बातों को ध्यान से सुना और जनहित के मुद्दों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इस भेंट को राजनीतिक पंडित राज्य के लिए एक सकारात्मक संकेत मान रहे है।

पाठको के लिए

मान्यवर पाठकगण

१. दैनिक इंडिया वार्ता समाचार पत्र हेतु अपने व्यक्तिगत या संस्थान की ओर से प्रकाशनार्थ लेख/समस्याएं व समाचार हमें भेजे व प्रति दिन नियमित रूप से समाचार पत्र प्राप्त करने को कार्यालय से सम्पर्क करे।

२. समाचार पत्र के बारे में आप के विचार व सुझाव आमंत्रित है।

३. नियमित पाठक बनने के लिए आपके द्वारा समाचार पत्र की सदस्यता ग्रहण करना प्रार्थनीय है।

४. व्यक्तिगत एवं व्यापारिक संस्थानो के तथा अन्य विज्ञापन आमंत्रित है।

सम्पादक

दैनिक इंडिया वार्ता

कार्यालय : मोहकमपुर खुर्द नियर आई आई पी हरिद्वार रोड देहरादून।

दूरभाष: 7500581414,9359555222